

not present in the House, naturally you would not know what has happened.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I am only referring to a convention.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Which convention?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Can the Government bypass the Parliamentary Standing committee and come straight to the House on an issue which ought to have been discussed there? That is my point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: In the committee?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: In the Parliamentary Standing Committee of Finance, it was not discussed.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): We are Members of the Standing Committee on Finance. These issues have not been discussed there but are listed here. That is why there is a surprise. *(Interruptions)*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I would like to draw your attention, Madam, to the convention with regard to the Parliamentary Standing Committee. I am afraid, what Mr. Gurudas is saying is not *ipso facto*. To my understanding, the standing instructions given by the speaker and the Chairman are that if a Bill is considered fit by the Speaker or the Chairman of the House to be referred to a Standing Committee, then and then only that Bill is considered in a Standing Committee. It would be a totally wrong interpretation to assume that each and every piece of legislation would automatically be discussed in the Standing Committee. I wanted to clarify this position.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What Mr. Pranab Mukherjee is saying is absolutely correct. If the Chairman or the Speaker feels that a particular Bill or legislation is to be referred to a Standing Committee, then only it would be referred. If the Chairman or the Speaker in their wisdom do not send it to the

Standing Committee, it would directly come to the House. As far as the Depository Bill is concerned, it was cleared by the Business Advisory Committee. कल आप नहीं थे मीटिंग में, आपने नहीं देखा कि क्या डिस्क्रशन हुआ। डिस्क्रशन एनार्जस हो गया है। अब यह मैटर क्लोज हो गया। Now we are taking up zero Hour mentions. Shri Bratin Sengupta, not here. Shri Salim?

[The Vice-Chairman (Shri Ajit P. K. Jogi) in the Chair]

RE. POLICE FIRING IN BANARAS HINDU UNIVERSITY

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं एक गंभीर विषय की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी जो केन्द्र सरकार की एक संस्था है, वहाँ पर जो गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है उस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, आप जानते हैं कि वहाँ फायरिंग हुई और 4 विद्यार्थी शहीद हुये और आज भी वह विश्वविद्यालय बंद पड़ा हुआ है और होस्टल खाली कर देने के लिये कहा गया है। महोदय, पिछले कई बरसों से तमाम विश्वविद्यालयों में जो नीति चलाई जा रही है और उससे जो स्थिति पैदा हो रही है, उससे विद्यार्थियों में काफ़ी असंतोष है। चाहे वह शिक्षा के मुद्दे के बारे में हो, चाहे वह फीस के बारे में हो, चाहे वह दूसरी चीजों के बारे में हो, वहाँ बहुत असंतोष है। महोदय, आपको मालूम है कि हमने कई बार इस इशू को यहाँ पर उठाया है। पिछले 5 सालों में जिस तरह से विश्वविद्यालयों की ग्रंट्स को फ़्रीज किया गया है, उससे इस तरह की शिकायत विद्यार्थियों में पैदा हुई है और वे सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन उनको रोकने का रास्ता यह नहीं है कि पुलिस ऐंथारिटी इंटरवीन करे और गोली चले और स्टूडेंट्स मारे जाएं और होस्टल खाली कर दिये जाएं।

महोदय, विश्वविद्यालय को बंद करके या होस्टल खाली करवाकर हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालय चालू रहने चाहिये और विद्यार्थी वहाँ होने चाहिये। विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिये आपको कोशिश करने पड़ेगी, एच-आर-डी० मिनिस्ट्री को इंटरवीन करना पड़ेगा क्योंकि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। महोदय, यह स्थिति सिर्फ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की नहीं है बल्कि दूसरे विश्वविद्यालयों में भी वही स्थिति होने जा रही है। दूसरी जो स्टेट

کرتے ہیں تو اس سمسٹیا کا اسماء دھان نہیں
ہوگا۔ اسماء دھان ہم کوئی چلا کر نہیں
کر سکتے ہیں۔

موجودہ میں اپنے مادہ میں سے بنارس
ہندو یونیورسٹی کو جانور کرنے کی مانگ کرتا
ہوں میں یہ بھی مانگ کرتا ہوں کہ وہ دیا رھیں
کی مانگیں پوری ہوں۔ میں یہ بھی مانگ کرتا ہوں
کہ وہاں جو فائرنگ ہوئی تھی اسی جیل میں
انکو انکری کر لیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ سولہ
اس معاملے میں جلد سے جلد انکری کر کے
جہازوں کے استفسار کو دور کرے۔

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): वहां बहुत खराब हो गई है और वह उत्तर प्रदेश सरकार ने... (व्यवधान)

श्री विष्णु कांत शास्त्री (उत्तर प्रदेश): मैं यह बोलना चाहता हूँ कि... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): सास्त्री जी, बिना अनुमति के न बोलें... (व्यवधान) कृपया बिना अनुमति के न बोलें।... (व्यवधान) इससे सम्बद्ध कर लें अपने आपको, सभापति महोदय ने आपको अनुमति नहीं दी है।... (व्यवधान) श्री ईश दत्त जी बोलिये। ... (व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): हमारे साथी श्री सलीम साहब ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सही है और मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। मान्यवर, मासूम विद्यार्थियों पर वहां गोली चलाई गई जिसमें चार विद्यार्थी मारे गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसने वहां कर एजीटेशन का रूप धारण कर लिया है और सरकार इसके गंभीरता से नहीं ले रही है। काशी विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। छात्रों को छात्रवास से बाहर निकाल दिया गया है और पठन-पाठन बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि सरकार इसके गंभीरता से ले, इसमें हस्तक्षेप करे ताकि वह जो आन्दोलन है यह आगे

ने बढ़ने पाए और विश्वविद्यालय में पठन-पाठन का क्रम शांतिपूर्वक चल सके।

श्री एस० एस० आहलुवालिया (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मोहम्मद सलीम द्वारा उठाए गये मुद्दे का पूरी तरह साथ देता हूँ और आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि कुछ दिन पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर वक्तव्य रखते हुये कहा था कि यह राज्य डिजस्टर की तरफ जा रहा है और उनका कौं हो रही है, लॉलेसनेस है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि वहां जो गैर जिम्मेदार लोगों ने विश्वविद्यालय के प्रांगण में गोली चलाने का आदेश दिया, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? वहां केन्द्र सरकार का गृहपति शासन चल रहा है। इस संबंध में केन्द्र सरकार सदन फटल पर एक वक्तव्य रखे और बताए कि ऐसे अपसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई शासन ने की है जिन्होंने ऐसे आदेश दिये और गोली चलावाई और पूरा विश्वविद्यालय व छात्रवास बंद कर डाला गया और सील कर दिया गया। मैं ज्युडिशियल इक्वायरी की मांग करता हूँ कि वहां पर तुलना ज्युडिशियल इक्वायरी के लिये एक कमीशन बैठायी जाए और इक्वायरी की जाए कि किन हालातों में गोली चलाने के आदेश दिये और वहां पर छात्रों को हताहत किया गया।

श्री नरेन्द्र मोहन: वहां ऐसे कोई हालात थे ही नहीं, न इतनी हिंसा थी कि पुलिस को गोली चलानी पड़ती। जो गोली चलाई गई वह बिल्कुल गलत तरीके से चलाई गई। एक उपनिषय है कि हमारे देश में किन हालातों में पुलिस गोली चलाएगी। ऐसी कोई स्थिति थी ही नहीं बनारस के अंदर। मैं मांग करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्याधीश के द्वारा इस प्रकार की जांच कराई जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। सब बोल नहीं सकते। जितने माननीय सदस्य खड़े हैं इससे इनको सम्बद्ध मान लिया जाता है।... (व्यवधान)

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश): बात यह है कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में जो कुछ छात्रों के साथ हुआ है और जो वहां के पुलिस अपसरों ने किया है उनके खिलाफ कानूनी दोषी अधिकारियों को सजा होनी चाहिये और उन तमाम अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। 14 छात्र उसमें घायल हुये हैं। इससे बड़ी ज्यादाती यूनिवर्सिटी के लोगों पर और स्टूडेंट पर क्या हो सकती है। आप दोषी अधिकारियों पर फौरन एक्शन कराइये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल): मानीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे चरित्र संसद सलीम साहब ने जो मुद्दा उठाया है, मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करती हूँ। इस तरह से शिक्षा संस्थानों में पुलिस को बुला कर मनमानी करना और छात्रों को बेमौत मारे जाने के लिये विवश करना, यह बिल्कुल गलत है और मैं इसकी न्यायिक जांच की मांग करती हूँ।

श्री मोहम्मद मसूद खान (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं 23 तारीख को इस घटना के मौके पर गया था। मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। जब पुलिस से भगदड़ मची तो कुछ लोग एक डॉक्टर के मकान पर चले गये और वहाँ पुलिस घुस गई। कुछ लड़के छत पकड़ कर नीचे उतर रहे थे, पुलिस ने उनके सिर पर ऐसा मारा कि वे वहीं उलट गये और मर गये। वह कॉलेज जहाँ 12—14 साल के लड़के ट्रेनिंग केलिये आते हैं, वहाँ होस्टल में घुस कर उनको जगा कर उनको पीटते हुये वे बाहर ले गये। न वहाँ प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाया था और न किसी और ने बुलाया था। ... (व्यवधान) ... मान्यवर, वहाँ एन्डीएम खुद पिस्तौल चला रहा था। ऐसे सूते हाल में दोषी लोगों को सजा दी जाए ताकि फिर ऐसी घटना न घटे।

آلٹری محمد مسعود خان اتر پردیش :
 مہودے میں ۲۳ تاریخ کو اس گھٹنا کے موقع
 پر گیا تھا۔ میں دو باتیں جانا چاہتا ہوں جب
 پولیس سے جگدڑ مچی تو کچھ لوگ ایک
 ڈاکٹر کے مکان پر چلے گئے اور وہاں پولیس
 گھس گئی کچھ لڑکے چھت پر کھڑے ہو کر نیچے اتر
 رہے تھے پولیس نے ان کے سیر ایسا مارا کہ
 وہ وہیں الٹ گئے اور مر گئے وہ لالچ
 جہاں بارہ چودہ سال کے لڑکے ٹریننگ
 کے لئے آتے ہیں وہاں ہو سٹل میں قصور
 آرائیوں جلا کر اٹکے بیٹھے ہوئے تھے باہر

کئے گئے وہاں پر انسپل نے پولیس کو بلایا
 اور نہ کسی اور نے بلایا تھا۔ "بمبار خلت"
 مانیفور وہاں ۱۷-۱۸ ڈی۔ ایم خود ہسٹل
 چلے رہا تھا ایسی صورت حال میں درستی ہوگئی
 کونسلر اوی جیائے تانہ پھر ایسی گھٹنا نہ کھئے

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P. K. JOGI): Gurudasji, be very, very brief.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, Uttar Pradesh is under Presidential rule. If anything happens there, it comes on the shoulders of the Central government. Since the Governor is the administrator and Presidential rule is there, the Central Government cannot absolve itself of the responsibility of the atrocities and repression that have been let loose. Therefore, the Central Government must tell the House what it is going to do to restrain the lawlessness in Uttar Pradesh as we see in the reckless police firing in Varanasi. I want a statement. And, I want the Central Government to pull on. Otherwise, there is going to be serious anarchy there. There is already anarchy, and there is likely to be a greater anarchy. And, Sir, the Governor must be restrained.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आप को सम्बद्ध करना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह जी ने इस मामले को पहले भी उठाया था। हमारी पार्टी का एक दल भी वहाँ पर गया था। किस प्रकार की ज्यादतियाँ न केवल बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी में बल्कि उसके आपस-पास के कॉलेजों में हुई हैं, उससे पूरे उत्तर प्रदेश में और विशेषतया पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ा संतोष फैल रहा है। इसीलिये मैं भी वह मांग करता हूँ कि इस पर गृह मंत्री द्रुत अपना एक स्टेटमेंट इस सदन में दें कि वहाँ क्या स्थिति है?

श्रीमती बीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो मुझ सलीम साहब ने उठाया है, उससे मैं स्वयं को सम्बद्ध करती हूँ। वह बड़े दुख और अपसेस की बात है लेकिन जब हम जांच की मांग कर रहे हैं तो जांच की कोई सम्भव-सीमा तब की जानी चाहिये कि इतने समय के अंदर जांच हो और वहाँ पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, सलीम साहब ने जी बी-एच-यू के सिलसिले में मुझ उठाया है, मैं इससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ और इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि कई सेंट्रल युनिवर्सिटीज़ में इस तरह के वाक्यात हो चुके हैं और इन सेंट्रल युनिवर्सिटीज़ में

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): आप इसी तक सीमित रहिए अपने आप को।

श्री मोहम्मद आज़म खान: जी। यूनिवर्स के ऑफिस बीयरस दिल्ली में एक जगह बैठे हैं और उन्होंने खुद भी चिंता व्यक्त की है। बी-एच-यू और एम-यू, दोनों में इस तरह के हालात पिछले चार-पाँच सालों से चल रहे हैं। इसकी ज्यूडीशियल इनक्वायरी की मांग हुई है और दोनों ने मिल कर एक बार वह मांग की थी कि बी-एच-यू और एम-यू के कैम्पस में होने वाली इन सारी डिस्टर्बेंसेज के लिए बुनियादी जिम्मेदार कौन है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Do not mention the names of other Universities.

श्री मोहम्मद आज़म खान: तो मैं चाहता हूँ कि सी-बी-आई की जांच अगर हो जाए तो सही हालात का अंदाज़ा हो जाएगा। इस विषय से सम्बद्ध करते हुए मैं इस मामले की सी-बी-आई जांच की मांग करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): मैं समझता हूँ कि वह अत्यंत गंभीर मसला है और सभी पार्टियों के सदस्यों ने इसे उठाया है इसलिए हासन इसकी ओर ध्यान दें। गृह मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी इस पर जरूर विचार करें।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (उजस्थान): इस पर एक बसतब्य माना चाहिए।

श्री एस-एस-अहलुवालिया: हमने स्टेटमेंट की मांग की है और न्यायिक जांच की मांग की है।

RE: NEED FOR O.N.G.C. TO EXPLOIT THE NATURAL GAS AVAILABLE ALONG INDO-PAK BORDER

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (उजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत अहम सवाल की ओर दिलाना चाहता हूँ। उजस्थान के जैसलमेर जिले में पाक बॉर्डर पर बहुत बड़े गैस के भंडार हैं। यह बात कई वर्षों से कही जा रही है और मांग की जा रही है।

सरकार ने भी विदेशी ड्रिलिंग कंपनियों को बुलाकर इसमें पहले काम शुरू करवाया था, उस समय भी शंकाएं व्यक्त की गयी थीं कि जान-बूझकर तथ्यों को प्रकट होने से रोका जा रहा है और ऐसी जगहों पर कुंपें खोदे गये जहाँ तेल गैस की संभावना नहीं थी और रिपोर्ट आ गयी। वहाँ का काम खत्म हो गया। अब तो यह मान लिया गया है, इंटरनेशनल कंपनियों ने भी मान लिया है कि वहाँ पर विशाल गैस के भंडार हैं और ऐसे भी भंडार हैं जो हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की सीमाओं के आर-पर फैले हुए हैं। पाकिस्तान सीमा से दो किलोमीटर दूर वहाँ एक बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनरी का कारखाना खुला हुआ है। वहाँ से वे प्रतिदिन डेढ़ मिलियन क्यूबिक मीटर गैस निकालते हैं और उसे फ्रैक्ट करके एक फ्रैक्ट प्लांट है, उसको फ्रीज करते हैं। ओ-एन-जी-सी ने भी यह मान लिया गया है कि वह रिसेर्स हिन्दुस्तान की सीमा में भी है। अगर ओ-एन-जी-सी तत्काल पहल करे तो वहाँ से एक मिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रतिदिन निकाली जा सकती है। अभी तक जैसलमेर इलाके में जितनी गैस प्लांट के आधार पर बिजली बन रही है, उस सबकी वह पूर्ति करेगा, इससे भी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि शीघ्र ओ-एन-जी-सी के सुपुर्द यह काम किया जाए या और भी किसी से सलाह लेनी हो तो लें और उस क्षेत्र में जो पाकिस्तान से लगा हुआ गैस भंडार है, वहाँ अपना काम शुरू करके गैस प्राप्त करने की कोशिश की जाए।

श्री सतीश अग्रवाल (उजस्थान): महोदय, मैं भी श्री सुन्दर सिंह भंडारी जी के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ और इसके लिए सरकार से पुनः मांग करता हूँ।

एस-एस-अहलुवालिया (बिहार): महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूँ। हमारे वहाँ जब से सैटलाइट लगे हैं, उससे हम मैचिंग कर सकते हैं कि कहां तेल है और कहां तेल नहीं है, कहां खनिज पदार्थ है। ओ-एन-जी-सी उसका प्रयोग नहीं कर रहा है और यह